

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 534)

28 कार्तिक 1930 (श0) पटना, बुधवार, 19 नवम्बर 2008

सं0 2/सी-10141/08 का0 11825 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

10 नवम्बर 2008

श्री विजय कुमार शर्मा (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक 172 / 04, 55 / 08 संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार बन्द करने संबंधित निर्णय के पश्चात् बिना सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किये बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को मल्टी स्टेट कॉ—आपरेटिव सोसाईटी एक्ट के तहत् केन्द्रीय निबंधक सहकारिता कृषि मंत्रालय भारत सरकार को बैंक का निबंधन करने हेतु निदेश देने संबंधी घोर कदाचार एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है।

- 2. अतः सरकार के निर्णयानुसार श्री शर्मा, कोटि क्रमांक 172/04 संयुक्त सचिव सहकारिता विभाग को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।
- 3. श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्णय है, जिसपर अलग से कार्रवाई की जायेगी।
 - 4. निलम्बन की अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय आयुक्त सहरसा प्रमंडल कार्यालय होगा।
- 5. श्री शर्मा को निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री विजय कुमार वर्मा (बि०प्र०से०) एवं अन्य संबंधितों को दे दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

सं0 2/सी-10141/08 का0 11824

संकल्प

10 नवम्बर 2008

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक 686 / 04, 528 / 08 अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार बन्द करने संबंधित निर्णय के पश्चात् बिना सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किये बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को मल्टी स्टेट कॉ—आपरेटिव सोसाईटी एक्ट के तहत् केन्द्रीय निबंधक सहकारिता कृषि मंत्रालय भारत सरकार को बैंक का निबंधन करने हेतु निदेश देने संबंधी घोर कदाचार एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है।

- 2. अतः सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंह (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक 686 / 04, 528 / 08 अवर सचिव, सहकारिता विभाग को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम –9 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।
- 3. श्री सिंह के बिरूद्ध बिभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्णय है। जिसपर अलग से कार्रवाई की जायेगी।
 - 4. निलम्बन की अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय आयुक्त सहरसा प्रमंडल कार्यालय होगा।
- 5. श्री सिंह को निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री जितेन्द्र कुमार सिंह (बि०प्र०से०) एवं अन्य संबंधितों को दे दी जाय।

> बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

सं0 2 / सी3–30119 / 93 / का0 11525 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

27 अक्तूबर 2008

श्री रामरूप सिंह (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक 730/99, 228/04 तत्कालीन उप समाहर्ता—सह— प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, सहरसा के विरुद्ध प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन अविध के दौरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने/निदेशालय द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंधन करने /वरीय संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय द्वारा जिला सांख्यिकी कार्यालय, हाजीपुर वैशाली को किये गये औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति पाये गये कर्मचारियों का बगैर मुख्यालय के आदेश प्राप्त कर अपने स्तर से निर्णय लेकर अनुपस्थित अविध का वेतन भुगतान करने/वरीय पदाधिकारियों का आदेश की अवहेलना करने से संबंधित आरोप निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

निदेशक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इसके आलोक में निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम –14 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है:–

- 1. निन्दन की सजा। (1993-94)
- 2. असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि की रोक।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रामरूप सिंह (बि०प्र०से०) सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, सहरसा एवं अन्य संबंधितों को दे दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

सं0 2 / सी3—10159 / 06 / का0 11826 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प 10 नवम्बर 2008

श्री अल्लामा मोख्तार, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक 2555/99, 1409/04 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, भूख के कारण श्रीमती लालती देवी द्वारा आत्महत्या करने, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने आदि आरोप, जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक —2839 दिनांक 02.08.06 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

2. उपर्युक्त आरोपों पर श्री मोख्तार के पत्रांक -30 दिनांक 04.12.2006 से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उस पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 837 दिनांक 12.02.07 द्वारा प्राप्त मंतव्य की सम्य्क समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री मोख्तार को उपर्युक्त आरोपों के लिये सरकार स्तर पर दोषी पाया गया और विभागीय संकल्प संख्या 5877 दिनांक 02.06.08 द्वारा दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड दिया गया। श्री मोख्तार की सेवा संपुष्ट नहीं होने के कारण मामले पर पुनर्विचार करते हुए श्री मोख्तार को पूर्व में दिये गये दंड को विलोपित करते हुए इनके दो वर्षों के लिये देय तिथि से प्रोन्नित पर रोक संबंधित दंड दिया जाता है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अल्लामा मोख्तार निलंबित पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना एवं अन्य संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

2/सी0-109/08 का0 11706 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

> संकल्प 3 नवम्बर 2008

श्री अवधेश पाण्डेय, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 355/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी—सह—अंचल अधिकारी, इस्लामपुर (नालंदा) के विरूद्ध प्रतिवेदित गवन संबंधी आरोप एवं इनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड संख्या 26/03 दिनांक 27.05.03 की धारा 409,420,120 (वी०) भा० द० वि० को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में संसीमीत किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (ग) में विहित प्रावधानों के तहत श्री पाण्डेय को विभागीय संकल्प संख्या 159 दिनांक 08.02.08 द्वारा दिनांक 10.01.08 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलम्बित किया गया।

श्री पाण्डेय द्वारा उनके विरूद्ध उपर्युक्त दर्ज थाना कांड में ए०सी०जी०एम० के न्यायालय में संज्ञान के विरूद्ध आवेदन किया गया, जिस पर विचार नहीं होने के कारण उनके द्वारा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिलसा (नालन्दा) के न्यायालय में क्रिमनल रिभिजन 29/08 दायर किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्न प्रकार है :--

From perusal of above evidences it appears that the petitioner has no role in the alleged affence, rather he gave notice to the contractor Mahesh Prasad to deposit the rest amount in Government treasury and when the said contractor did not deposit the side amount the petitioner has made order to realize the said amount by filling certificate case and F.I.R against the said contractor.

Accordingly, the impugned order is suffers from jurisdiction and legal error. Therefore the impugned order against petitioner's is set aside and the instant revision petition is allowed in favors of petitioner.

उपर्युक्त पारित आदेश के आलोक में मामले की पूर्ण समीक्षोपरांत श्री पाण्डेय को दिनांक 24.10.08 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है। निलम्बन अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अवधेश पाण्डेय, कोटि क्रमांक 355/04 मुख्यालय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

> बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

सं0 2/सी.3-30135/2000 का0 11920 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प 12 नवम्बर 2008

श्री अनिमेष कुमार (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक 1279/04 तत्का० प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदवन्तनगर भोजपुर के विरूद्ध विधायक योजनाओं के अभिकर्त्ता के रूप में जीप चालक को अभिकर्त्ता नियुक्त करने, चुनाव आचार संहिता का उल्लंधन करने, मत—पेटी की रंगाई—पुताई में गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं आहर मरम्मती में धिटया किस्म के समानों का उपयोग करने संबंधित प्रतिवेदन आरोपों की समीक्षोपरान्त आरोपों को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 49 (ए०) में निहित, प्रावधान के तहत श्री कुमार को विभागीय संकल्प संख्या 1661 दिनांक 28.03.2001 द्वारा निलम्बित किया गया। आरोपों की जाँच हेतु संकल्प संख्या 1686 दिनांक 28.03.2001 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर आयुक्त पटना प्रमंडल पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं सुसंगत कागजातों के पूर्ण सम्क्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप श्री कुमार को दिनांक 24.10.08 से निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसुचित किया जाता है :--

- 1. संचायात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि की रोक।
- 2. देय तिथि से तीन वर्षों के लिये प्रोन्नति पर रोक।
- 3. निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति श्री अनिमेष कुमार बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 1279/04 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 534-571-डी0टी0पी0।